



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092020-221874  
CG-DL-E-22092020-221874

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254]  
No. 254]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2020/भाद्र 31, 1942  
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2020/BHADRA 31, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2020

मामला सं. ए डी (ओआई) 35/2020

**विषय :** चीन जन.गण. तथा कोरिया गणराज्य से “अनट्रीटेड फ्यूड सिलिका” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

**फा. सं. 6/40/2020-डीजीटीआर.**—मै. काबोट सनमार लिमिटेड (जिसे यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. तथा कोरिया गणराज्य (जिन्हें यहां आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “अनट्रीटेड फ्यूड सिलिका” (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” या “पीयूसी” भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

**क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)**

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "अनट्रीटेड फ्यूमड सिलिका" है। सिंथेटिक सिलिका को सिलाने यौगिक के वैपॉर फेज फ्लेम हाइड्रोलिसिस से विनिर्मित किया जाता है और इसे आम तौर पर फ्यूमड सिलिका के रूप में जाना जाता है। इस किस्म की सिंथेटिक सिलिका अपने कार्य और विनिर्माण प्रक्रिया तथा आवश्यक कच्ची सामग्रियों के कारण अन्य सिलिका से भिन्न होती है। यद्यपि, अन्य सिंथेटिक सिलिका लिक्विड फेज में सिलिकेट विलेयन से निर्मित होती हैं, तथापि, फ्यूमड सिलिका अत्यधिक उच्च ताप पर गैस फेज से विनिर्मित होती है।
4. फ्यूमड सिलिका को अनट्रीटेड फ्यूमड सिलिका या ट्रीटेड फ्यूमड सिलिका के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अनट्रीटेड फ्यूमड सिलिका 1800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लेम में क्लोरोसिलाने फीडस्टॉक के फ्लेम हाइड्रोलिसिस द्वारा बनती है। इस प्रक्रिया में एक अद्वितीय संरचना की सिलिका उत्पादित होती है जिसमें चेन जैसे एग्रीगेट्स और एग्लोमेरेट्स होते हैं।
5. अनट्रीटेड फ्यूमड सिलिका का एक बड़ा विशिष्ट सतह क्षेत्र होता है। 150 या 200 या 300 या 380 एम<sup>2</sup>/जीएम जैसे अपने सतह क्षेत्र मूल्य के आधार पर अनट्रीटेड फ्यूमड सिलिका को विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त अलग-अलग ग्रेडों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे लोकप्रिय ग्रेड 200 एम<sup>2</sup>/जीएम है, जिसके अनेक अनुप्रयोग होते हैं।
6. यह फ्री-फ्लोविंग पावडर उत्पाद है, जिसके व्यापक अनुप्रयोग होते हैं। अनट्रीटेड फ्यूमड सिलिका को प्रणालियों में फ्री फ्लो की विशेषता में सुधार करता है और भेषजों में फ्री फ्लो और टेबलेट एजेंट के रूप में तथा खाद्य पदार्थों तथा कृषि रसायन में एंटी केकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग तरल, स्वाद और सुगंधों के वाहक के रूप में भी होता है। संबंधित उत्पाद किलोग्राम या एमटी के रूप में व्यक्त निवल भार के अनुसार बेचा जाता है।
7. फ्यूमड सिलिका या सिलिकॉन डाईऑक्साइड को अध्याय-28 के अंतर्गत उपशीर्ष 28112200 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। अनट्रीटेड फ्यूमड सिलिका का सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 28 के उपशीर्ष 28112190, 28391900 और अध्याय 34 के उपशीर्ष 34049090 के अंतर्गत भी विभिन्न एच एस कोड के अधीन भारत में आयात किया जा रहा है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक प्रकृति के हैं और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।

**ख. समान वस्तु**

8. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में निर्यातित संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयातित वस्तु के तकनीकी विनिर्देशनों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

**ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

9. यह आवेदन मै. काबोट सनमार लिमिटेड. द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने देश में संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक होने का दावा किया है और आवेदक का उत्पादन समान उत्पाद का कुल भारतीय उत्पादन बनता है। आवेदक ने दावा किया है कि न तो उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित हैं।
10. उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक का भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है और आवेदन नियमावली के नियम 2 (ख) और 5(3) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है।

**घ. कथित पाटन का आधार****क. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य**

11. आवेदक ने दावा किया है चीन जन.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य को नियमावली के नियम 7 के अनुबंध-1 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। इस उत्पाद को अधिकांशतः चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ और जापान द्वारा जांच अवधि (पीओआई) में उत्पादित और निर्यातित किए जाने का दावा किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि भारत को यूरोपीय संघ से औसत निर्यात कीमत को चीन जन.गण. हेतु सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए माना गया है। तथापि, विस्तृत जांच और परीक्षण होने तक जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ चीन हेतु सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर और उसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक (एसजीए) व्यय तथा तर्कसंगत लाभ हेतु आवश्यक समायोजन के साथ परिकलित किया गया है।

**ख. कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य**

12. आवेदक ने दावा किया है कि उन्हें कोरिया गणराज्य के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत नहीं मिल पाई थी। आवेदक ने कोरिया में उत्पादन लागत के अनुमानों को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक (एसजीए) व्यय सहित विधिवत रूप से समायोजित करके उनके आधार पर कोरिया में सामान्य मूल्य का दावा किया है। तथापि, विस्तृत जांच और परीक्षण होने तक जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ कोरिया गणराज्य हेतु सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर और उसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक (एसजीए) व्यय तथा तर्कसंगत लाभ हेतु आवश्यक समायोजन के साथ परिकलित किया गया है।

**ग. निर्यात कीमत**

13. निर्यात कीमत को वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों के आधार निर्धारित किया गया है। निर्यात कीमतें सीआईएफ मूल्य हैं जबकि सामान्य मूल्य कारखाना द्वार स्तर पर है। निर्यात कीमतों को समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय माल भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और गैर वापसी योग्य वैट (केवल चीन के लिए) हेतु समायोजित किया गया है।

**घ. पाटन मार्जिन**

14. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है ताकि पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सके। इस प्रकार निर्धारित पाटन मार्जिन प्रत्येक संबद्ध देश के लिए न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि भारत में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध देशों से उत्पाद का पाटन हो रहा है।

**ङ. क्षति एवं कारणात्मक संबंध**

15. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदक ने समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, भारी कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और उत्पादन, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सा, क्षमता उपयोग और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है।

**च. पाटनरोधी जांच की शुरुआत**

16. घरेलू उद्योग के द्वारा या उसकी ओर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरुआत करते हैं।

**छ. संबद्ध देश**

17. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. तथा कोरिया गणराज्य हैं।

**ज. जांच की अवधि (पीओआई)**

18. वर्तमान जांच में जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 (12 महीने) की है। तथापि क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2016- 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017- 31 मार्च, 2018, , 1 अप्रैल, 2018 - 31 मार्च, 2019 और पी ओ आई की अवधियां शामिल होंगी।

**झ. प्रक्रिया**

19. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

**ञ. सूचना प्रस्तुत करना**

20. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों [adg12-dgtr@gov.in](mailto:adg12-dgtr@gov.in), [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in), [dd17-dgtr@gov.in](mailto:dd17-dgtr@gov.in) तथा [ad11-dgtr@gov.in](mailto:ad11-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
21. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

**ट. समय-सीमा**

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 37 दिनों के भीतर ईमेल पतों [adg12-dgtr@gov.in](mailto:adg12-dgtr@gov.in), [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in), [dd17-dgtr@gov.in](mailto:dd17-dgtr@gov.in) तथा [ad11-dgtr@gov.in](mailto:ad11-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।
26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे डी जी टी आर की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) को नियमित रूप से देखते रहें।

**ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) तथा इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
28. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
29. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

30. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
31. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशिकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
32. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
33. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
34. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### **ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

35. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलैक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक फाइल को रखे जाने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं।

#### **ढ. असहयोग**

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बी.बी.स्वैन , विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

### **MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

(Directorate General of Trade Remedies)

#### **INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd September, 2020

(Case No. AD (OI) – 35/2020)

**Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Untreated Fumed Silica from China PR & Korea RP.**

**F. No. 6/40/2020-DGTR.**—M/s Cabot Sanmar Limited (hereinafter also referred to as the "Applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") seeking initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Untreated Fumed Silica (hereinafter also referred to as the "subject goods" or "product under consideration" or "PUC") originating in and exported from China PR & Korea RP (also referred to as "subject countries") in accordance with Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (herein also referred to as the "Act") and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the "Rules").



2. The Applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to dumped imports from the subject countries and has requested for imposition of the anti-dumping duties on the import of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

**A. Product under Consideration (PUC)**

3. The product under consideration in the application is “untreated fumed silica”. Synthetic silica manufactured from a vapour phase flame hydrolysis of a silane compound, is popularly known as fumed silica. This type of synthetic silica is different from other silica by its functionality and manufacturing process and the raw materials needed. While other synthetic silicas are made from silicate solution in a liquid phase, fumed silica is manufactured in a gas phase at a very high temperature.
4. Fumed silica is classified as untreated fumed silica and treated fumed silica. Untreated fumed Silica is made by the flame hydrolysis of Chlorosilane feedstock in an oxygen hydrogen flame at temperatures of 1800 deg C. This process allows production of the silica with unique structure comprising of chain like aggregates and agglomerates.
5. Untreated fumed silica has a large specific surface area. Depending upon its surface area values such as 150 or 200 or 300 or 380 m<sup>2</sup>/gm. the untreated fumed silica is classified as different grades suitable for different applications. The most popular grade is 200m<sup>2</sup>/gm, used in variety of applications.
6. It is free-flowing powdered product, used for wide applications. Untreated Fumed Silica improves free flow properties in solid systems and used as a free flow and tableting agent in pharmaceuticals and an anti-caking agent in foods and agrochemicals. It also used as a carrier for liquid flavours and fragrances. Product concerned is sold in terms of net weight expressed in terms of kg or MT.
7. Fumed Silica or Silicon di-oxide is classified under Chapter 28, subheading 28112200. The untreated fumed silica is being imported into India under different HS codes also under subheading 28112190, 28391900 of Chapter 28 and 34049090 of Chapter 34 of the Customs Tariff Act, 1975. Customs classification is only indicative in nature and not binding on the scope of the investigation.

**B. Like article**

8. The Applicant has claimed that the subject goods exported to India are identical to the goods produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from subject country in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country

**C. Domestic industry and standing**

9. The application has been filed by M/s Cabot Sanmar Limited. The applicant has claimed to be the sole producer of the subject goods in the country and the production by the applicant constitutes total Indian production of the like product. The applicant has claimed that they have neither imported the subject goods from the subject countries nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject countries or any importer of the product under consideration in India.
10. On the basis of the information available, the Authority holds that the Applicant accounts for a major proportion in the Indian production and the application has been made by the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

**D. Basis of Alleged Dumping**

**a. Normal value for China PR**

11. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy, and the normal value should be determined in terms of Annexure I, Rule 7 of the Rules. The product is claimed to be majorly produced and exported from China PR, Korea RP, the European Union and Japan in the period

of investigation (POI). The applicant has claimed that the average export price from European Union to India be considered for determining Normal Value for China PR. However, pending detailed examination and scrutiny, the normal value for the purpose of initiation for China PR has been constructed on the basis of cost of production of domestic industry with due adjustment for selling general & administrative (SGA) expenses and reasonable profit.

**b. Normal value for Korea RP**

12. Applicant has claimed that they could not find price of subject goods in the domestic market of Korea RP. The, applicant has claimed normal value in Korea on the basis of estimates of cost of production in Korea, duly adjusted with selling, general and administrative (SGA) expenses. However, pending detailed examination and scrutiny, the normal value for the purpose of initiation for Korea RP has been constructed on the basis of cost of production of domestic industry with due adjustment for selling general & administrative (SGA) expenses and reasonable profit.

**c. Export Price**

13. The export price has been determined on the basis of transaction wise import data provided by Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S). The export prices being CIF value while the normal values being at ex-factory level, the export prices have been adjusted for, ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses, bank charges and non-refundable VAT (for China PR only).

**d. Dumping Margin**

14. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level so as to determine the dumping margin. The dumping margin so determined is above the de-minimis level for each of the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the product under consideration is being exported to India at price below normal value, resulting in dumping of the product from the subject countries.

**E. Injury and causal link**

15. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and also in relation to production and consumption in India, significant price undercutting, price underselling, price suppression, and deterioration in performance of the domestic industry in respect of production, domestic sales, market share, capacity utilization and return on capital employed. There is prima facie evidence that the dumped imports from subject countries are causing material injury to the domestic industry.

**F. Initiation of Anti-Dumping Investigation**

16. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**G. Subject countries**

17. The subject countries for the present investigation are China PR and Korea RP.

**H. Period of Investigation (POI)**

18. The period of Investigation (POI) for the present investigation is 1<sup>st</sup> April 2019 – 31<sup>st</sup> March 2020 (12 months). The injury investigation period will cover the periods 1<sup>st</sup> April 2016- 31<sup>st</sup> March 2017, 1<sup>st</sup> April 2017- 31<sup>st</sup> March 2018, 1<sup>st</sup> April 2018- 31<sup>st</sup> March 2019 and the POI

**I. Procedure**

19. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

**J. Submission of Information**

20. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address [adg12-dgtr@gov.in](mailto:adg12-dgtr@gov.in), [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in), [dd17-dgtr@gov.in](mailto:dd17-dgtr@gov.in) and [ad11-dgtr@gov.in](mailto:ad11-dgtr@gov.in). It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
21. The known exporters, their Government through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

**K. Time Limit**

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses [adg12-dgtr@gov.in](mailto:adg12-dgtr@gov.in), [adv11-dgtr@gov.in](mailto:adv11-dgtr@gov.in), [dd17-dgtr@gov.in](mailto:dd17-dgtr@gov.in) and [ad11-dgtr@gov.in](mailto:ad11-dgtr@gov.in) within 37 days from the date of receipt of the notice as per as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.
26. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of DGTR i.e. [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation.

**L. Submission of information on confidential basis**

27. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
28. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
29. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
30. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
31. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.



32. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
34. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**M. Inspection of Public File**

35. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

**N. Non-cooperation**

36. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority